

नवभारत टाइम्स

बेंगलुरु/चेन्नै समाचार

Hindi News » State News In Hindi » Other States News In Hindi » Bangalore/Chennai News In Hindi » Bengaluru Urbanisation Poses Threat As Major Part Of City Could Become Concrete

...तो साल 2025 तक 95% बेंगलुरु होगा पत्थर का शहर?

टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated: Sep 30, 2018, 04:15PM IST

Facebook, Twitter, Google+, Email, Comment, and Newsletter icons.



प्रतीकात्मक तस्वीर

बेंगलुरु

बेंगलुरु में जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है उसे देखकर पहले ही अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं था कि भविष्य में शहर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स ने शनिवार को इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर कर दी कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो साल 2025 तक शहर का 95% हिस्सा कंक्रीट का बन जाएगा। एक्सपर्ट्स ने शहर में हरियाली कम होने, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कमी और रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी

के बारे में चर्चा की।

Ad: Ready Set Health

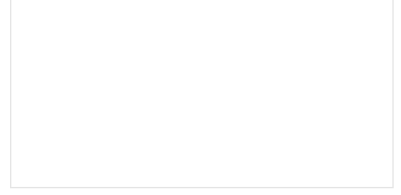
Ad: Health Sciences Institute

Recommended By Colombia

अलग-अलग रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन के कम से कम 500 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस के टीवी रामचंद्र ने बताया कि बेंगलुरु की झीलें मशरूम की तरह खड़े हो रहे अपार्टमेंट्स की वजह से सूख रही हैं। बिल्डरों और सरकार ने शहर सारी छोटी झीलों पर अतिक्रमण कर लिया है।

'बहाने बनाती है BBMP'

शहर के पर्यावरणविद समूह फ्रेंड्स ऑफ लेक्स के को-फाउंडर वी रामप्रसाद ने बताया कि झीलें कचरे का ढेर बन गई हैं क्योंकि बहुत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) का कलेक्शन सिस्टम खराब है। उन्होंने कहा, 'इस साल का स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो गया है लेकिन बीबीएमपी का उसकी ओर अनदेखी का रवैया डरावना है। बीबीएमपी कलेक्टर्स की कमी और खराब ऑटो टिपर्स का बहाना बनाकर अपने खराब प्रबंधन को छिपाती है।'



यह भी पढ़ें: पानी संकट: बेंगलुरु बनने जा रहा भारत का केपटाउन!

'कॉर्पोरेट्स से झीलों गोद लेने की अपील'

मल्लेस्वरम के विधायक सीएन अश्वथ नारायण ने कॉर्पोरेट्स से झीलों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज इतने सारे संगठन हैं और अगर सभी दो झीलों को गोद ले लें तो हम उन्हें फिर से जीवित कर सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने कॉर्पोरेट्स से झीलों को संभालने की अपील की थी।

'फंसाते हैं बिल्डर और ठेकेदार'

ऐडवोकेट और रेरा एक्सपर्ट एच शारदा ने बताया कि लोग लोन लेकर हर महीने 30 हजार से लेकर 1 लाख रुपये खर्च करके यह संपत्तियां खरीदना चाहते हैं लेकिन उनमें से कई कभी इनके मालिक नहीं होते। उन्होंने कहा कि खरीददार बिल्डर और ठेकेदारों के जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रेरा योग्य हो तो इस धोखाधड़ी को रोका जा सकता है लेकिन इसके न होने से कई लोगों के साथ धोखा होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को जागने की और एक रेरा कमिटी बनाने की जरूरत है जो यह सुनिश्चित करे कि अगर बिल्डर नियमों का उल्लंघन करता है तो संपत्ति के खरीददार और मालिक को खरीद की तारीख से लेकर कॉम्प्लिमेंट तक की कीमत दी जाए।